संख्या-168/2022/759/41-2022/33(बजट)/2021

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 मार्च 2022**

विषयः- जनपद वाराणसी शहर के अन्तर्गत् ओल्ड काशी के हबीबीपुरा वार्ड तथा चेतगंज वार्ड के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की परियोजना की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8423/6-1-1/(1244)/2021-22 दिनांक 26 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद वाराणसी शहर के अन्तर्गत् ओल्ड काशी के ओल्ड काशी के हबीबीपुरा वार्ड तथा चेतगंज वार्ड के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की परियोजना** हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 प्रखण्ड वाराणसी **को** कार्यदायी संस्था नामित करते हुये शासनादेश सं0 15/2022/आई/130314/2022/41-1002(001)/158/2021 दिनांक 07 जनवरी 2022 द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)
1	**हबीबीपुरा वार्ड**	उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0	रू0 488.83 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00 लाख
	चेतगंज वार्ड -1		रू0 469.89 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00 लाख
	चेतगंज वार्ड -2		रू0 350.87 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00 लाख

3- उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपरोक्त तीनों प्रायोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशियों के सापेक्ष अलग अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु प्रस्ताव के साथ प्रायोजना स्थल के फोटोग्राफ, प्रायोजना की टेण्डर लागत एवं टेण्डर लागत के सापेक्ष अन्य मदों का मदवार व्यय विवरण, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, निरीक्षण आख्या, पर्ट चार्ट, तकनीकी स्वीकृति, 24 बिन्दुओं की चेकलिस्ट के सापेक्ष सूचना एवं आवश्यक प्रपत्र आदि नहीं उपलब्ध कराये गये हैं।

4- वर्णित परिस्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रायोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि इस प्रतिबन्ध सहित अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं कि प्रायोजना की अगली किश्त की मांग प्रस्तुत करते समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, निरीक्षण आख्या, पर्ट चार्ट, तकनीकी स्वीकृति, 24 बिन्दुओं की चेकलिस्ट के सापेक्ष सूचना एवं आवश्यक प्रपत्र, प्रायोजना स्थल के फोटोग्राफ, प्रायोजना की टेण्डर लागत एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का मदवार व्यय विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त करने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रूपये लाख में)
1	**हबीबीपुरा वार्ड**	रू0 250.00 लाख
	चेतगंज वार्ड -1	रू0 250.00 लाख
	चेतगंज वार्ड -2	रू0 250.00 लाख

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0 15/2022/आई/130314/2022/41-1002(001)/158/2021 दिनांक 07 जनवरी 2022 द्वारा में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है। **उक्त के अतिरिक्त परियोजना की मूल स्वीकृति से संबंधित निविदा लागत के क्रम में कार्यों/लागत में कोई विचलन किया जाना अपेक्षित है तो उसके संबंध में नियमानुसार प्रायोजना के कार्य/लागत के पुनरीक्षण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2526/दस-सं0-बी-2-2526/दस-2014-10/77 दिनांक 26-8-14 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।**

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-46 वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या**-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020** दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी (जवाहर भवन) लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक , उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 वाराणसी ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in